



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022020-216417
CG-DL-E-26022020-216417

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2020/फाल्गुन 6, 1941

No. 55]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020/PHALGUNA 6, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2020

विषय : चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी)—आगे सम्मिश्रण (कंपाउंड) में प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं” के संबंध में पाटन-रोधी जांच।

फा. सं. 06/03/2019-डीजीटीआर.—विषय पाटन-रोधी जांच के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी की गयी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/3/2019-डीजीटीआर दिनांक 19.02.2020 की तरफ ध्यान आमंत्रित किया जाता है। उक्त जांच परिणाम का अनुच्छेद 120 इस प्रकार है, जिसे निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

पूर्व अनुच्छेद

120. कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन के कम मार्जिन और क्षति के मार्जिन के समान निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए संबंध वस्तुओं के पहुंच मूल्य और नीचे दी गई शुल्क सारणी के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बीच के अंतर के रूप में, बशर्ते पहुंच मूल्य कॉलम 7 में उल्लिखित मूल्य से कम है, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 द्वारा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9क, के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर लागू सीमा शुल्क के स्तर पर होगा।

संशोधित अनुच्छेद

120. कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन के कम मार्जिन और क्षति के मार्जिन के समान निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचना संख्या 33/2019-सीमा शुल्क दिनांक 26 अगस्त, 2019 के द्वारा अनंतिम शुल्क को लागू करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए संबंध वस्तुओं के पहुंच मूल्य और नीचे दी गई शुल्क सारणी के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बीच के अंतर के रूप में, बशर्ते पहुंच मूल्य कॉलम 7 में उल्लिखित मूल्य से कम है, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 द्वारा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9क, के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर लागू सीमा शुल्क के स्तर पर होगा। उपरोक्त के अधीन, प्रारंभिक जांच परिणाम, जिसे अधिसूचना संख्या 6/3/2019-डीजीटीआर दिनांक 12 जुलाई, 2019 को अधिसूचित किया था, की पुष्टि की जाती है।

2. उपरोक्त के अधीन, विषय पाटन-रोधी जांच के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी की गयी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/3/2019-डीजीटीआर दिनांक 19.02.2020 के अन्य सभी पहलू अपरिवर्तित हैं।

भूपिंदर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2020

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of "Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Resin—whether or not further processed into compound", originating in or exported from China PR and Korea RP.

F. No. 6/3/2019-DGTR.—Attention is invited to the Final Finding Notification No. 6/3/2019-DGTR dated 19.02.2020 issued by the Designated Authority in respect of the subject Anti-dumping Investigation. Paragraph 120 of the said Finding is, hereby, corrected as follows:

EARLIER PARA

120. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, for a period of five years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, as the difference between the landed value of the subject goods and the amount indicated in Col 7 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col 7. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

CORRECTED PARA

120. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, for a period of five years, from the date of imposition of provisional duties notified by the Central Government vide Notification No. 33/2019-Customs dated 26th August, 2019, as the difference between the landed value of the subject goods and the amount indicated in Col 7 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col 7. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975. Subject to the above, the Preliminary Finding notified vide notification No. 6/3/2019-DGTR dated 12th July, 2019 is hereby confirmed.

2. Subject to the above, all other aspects of the Final Finding Notification No. 6/3/2019-DGTR dated 19.02.2020 issued by the Designated Authority in respect of the subject Anti-dumping investigation remain unchanged.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority